टाइम्स रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की खराब स्थिति चिंताजनक है।

यह खराब प्रदर्शन हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और बौद्धिक क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रसिद्धि को चोट पहुंचाता है।

– हरिवंश चतुर्वेदी
डायरेक्टर, बिमटेक

भारत सरकार द्वारा देश के शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के प्रयासों को यूके की टाइम्स एजूकेशन द्वारा घोषित 2020 की विश्वविद्यालय रैंकिंग सूची से एक धक्का लगा है। पिछले एक दशक से मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे थे जिससे कि भारत के नामचीन विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय रैंकिगों में शीर्ष स्तर पर अपनी जगह बना सकें। पिछले साल लागू की गई इन्स्टीट्यूट ऑफ एंमीनेंस (आईओई) नामक बहुचर्चित योजना का तो यह प्रमुख उद्देश्य था कि देश के अच्छे विश्वविद्यालयों को ज्यादा स्वायत्तता दी जाये और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों को दस वर्षों के लिये एक हजार करोड़ रू. की वित्तीय सहायता दी जाये।

विश्व स्तर पर शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्रमुखतया तीन संस्थाओं द्वारा की जाती है यथा टाइम्स हायर एजूकेशन (टीएचई), शंघाई जियोटोंग यूनिवर्सिटी (एसजेटीयू) एवं क्विकरैली सायमण्ड्स (क्यू एस)। इन में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं मान्यता टाइम्स हायर एजूकेशन की दी जाती है जो कि पिछले 16 वर्षों से इसे संचालित करते रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि वर्ष 2020 की रैकिंग में 2012 के बाद पहली बार शीर्ष स्तरीय 200 विश्वविद्यालयों की सूची में किसी भारतीय विश्वविद्यालय का नाम नहीं है।

टाइम्स रैकिंग में वैसे तो दुनिया के शीर्षस्थ 1300 विश्वविद्यालयों में भारत के 56 विश्वविद्यालयों के नाम शामिल हैं और संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पांचवा और एशिया में तीसरा स्थान है। किन्तु इस तथ्य से हम यह निष्कर्स नहीं निकाल सकते कि विश्व स्तर पर हमारे विश्वविद्यालय अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस का एक कारण अन्य देशों की अपेक्षा हमारे विश्वविद्यालयों की संख्या का अधिक होना भी है।

2020 की टाइम्स रैंकिंग में भारत का ख्याति प्राप्त संस्थान इण्डियन इन्स्टीयूट ऑफ साइंस 50 स्थान नीचे गिर गया है। 1909 में जमसेतजी टाटा और मैसूर नरेश के प्रयासों से स्थापित इस संस्थान की रैंकिंग 2019 में 251–300 के ग्रुप में थी, जो कि इस बार 301–350 के ग्रुप में पहुंच गई है। इस संस्थान के अलावा आईआईटी, रोपड़ को 301–350 और आईआईटी, इन्दौर को 351–400 के ग्रुप में रैंकिंग दी गई है। अगर पुराने व प्रतिष्ठित आईआईटीयों को देखें तो आईआईटी, बोंबे, आईआईटी, खड़गपुर और आईआईटी, दिल्ली को 401–500 के ग्रुप में शामिल किया गया है। यह आश्चर्य की बात है कि पुराने आईआईटीयों को नये आईआईटी कड़ी चुनौती दे रहे हैं।

टाइम्स की रैंकिंग में शुरू से यूएसए की यूनिवर्सिटियों का दबदबा रहा हैं। इस बार भी शीर्षस्थ 10 यूनिवर्सिटियों में 7 और शीर्षस्थ 20 यूनिवर्सिटियों में 14 यूएसए की हैं। जिन शीर्ष 200 यूनिवर्सिटियां में भारत को स्थान नहीं मिला है, उनमें यूएसए की 60 यूनिवर्सिटियों शामिल हैं। कुल 1300 यूनिवर्सिटियों की सूची में यूएसए की 172 यूनिवसिर्टियां शामिल हैं। शीर्ष 200 यूनिवर्सिटियों की सूची में एशिया से पहला स्थान चीन का है, जिसकी 24 यूनिवर्सिटियां इस में शामिल हैं।

टाइम्स की रैंकिंग में यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आम तौर पर विश्व में पहले स्थान पर रही है। 2020 में भी इसे पहला स्थान मिला है। इस के बाद के नौ स्थानों पर कैलीफोर्निया इन्स्टी. (यूएसए), कैम्ब्रिज यूनि. (यू.के.), स्टैनफर्ड यूनि. (यूएसए), हार्वर्ड (यूएसए), येल (यूएसए), शिकागो (यूएसए) और इंपीरियल कॉलेज (यूके) हैं।

हर वर्ष टाइम्स तथा अन्य दो रैंकिंगों की सूची जारी होने पर हमें निराश होना पड़ता है। यह गिरावट या खराब प्रदर्शन हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और बौद्धिक क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रसिद्धि को चोट पहुंचाती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. प्रणव मुखर्जी ने अपने कार्यकाल में कई बार यह मुद्दा उठाया था कि इन विश्व सूचियों में हमारे विश्वविद्यालय शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में क्यों नही स्थान पाते हैं? यह भी एक चिंतनीय मुद्दा है कि भारत में शिक्षित अनेक भारतीय प्रोफेसर अमरीकी विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्तर पर रखे जाते हैं और उन्हें अनेक विश्वविद्यालयों में उच्च पदों पर भी बैठाया जाता है, किन्तु जिन भारतीय विश्वविद्यालयों से पढ़ कर उन्होंने नाम कमाया, वे विश्व स्तरीय रैकिंगों में पीछे रह जाते हैं? इस मुद्दे की गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिये।

भारतीय उच्च शिक्षा की विश्वस्तर पर दयनीय स्थिति से उबारने के कई प्रयास पिछले वर्षों में किये गये हैं। इनमें एक प्रमुख प्रयास था वर्ष 2016 में शुरू की गई एनआईआरएफ रैंकिंग, जो कि विश्वस्तरीय तो नहीं किन्तु इसे शुरू करने का प्रमुख मकसद भारतीय विश्वविद्यालयों को कुंभकर्णी निद्रा से जगा कर उन्हें रैंकिंग संस्कृति और विश्वस्तरीय के लिये तैयार करना था।

एक प्रश्न यह भी उठ सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के लिये राष्ट्रीय और विश्वस्तरीय रैंकिंगो में भाग लेना क्यों जरूरी है? ऐसा करने से उन्हें क्या मिलेगा? अगर गहराई से देखें तो मालुम पड़ेगा कि विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रहे विद्यार्थियो के आव्रजन का निर्णायक घटक मुख्यतया रैंकिंग होता है। पिछले 30 वर्षो में दुनिया ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की और तेजी से बढ़ी है। यूएसस, यूके, यूरोप, कनाडा और आस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा विदेशी विद्यार्थियो की फीस और उनके रहने–सहने के खर्चों से आता है। रैंकिगों की लोकप्रियता का दूसरा प्रमुख कारण है दुनिया भर से अत्यधिक प्रबुद्ध, रचनात्मक और शोध प्रतिभाओं को अपने–अपने देशों में आकर्षित करना। कहा जाता है कि आज के युग में पूंजी और श्रम के लिये विश्वयुद्ध नही होते किन्तु टेलेंट के लिये सभी देश मारामारी करते हैं। यूनिवर्सिटी रैंकिंग इन सभी कार्यो में बहुत मदद करती हैं।

भारत की उच्चशिक्षा में हर स्तर पर एक सवाल बार–बार उठता है कि विश्व रैंकिगों में हमारे विश्वविद्यालय में फिसड्डी क्यों हैं? आईआईटी, आईआईएम और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय संसाधनों कमी नही रहती किन्तु वे भी इन रैंकिगों में क्यों पिछड़ जाते हैं?

विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा रैंकिंगो में शिक्षण, अनुसंधान, उद्योगों से होने वाली आय और अन्तर्राष्ट्रीयकरण के प्रमुख आधारों पर रैकिग निकाली जाती है। टाइम्स रैकिंग में 30 प्रतिशत जोर शिक्षण की गुणवता पर, 60 प्रतिशत जोर अनुसंधान और साइटेशन पर, उद्योगों से आय पर 2.5 प्रतिशत और अन्तर्राष्ट्रीयकरण पर 7.5 प्रतिशत जोर दिया जाता है। 2020 की की टाइम्स रैंकिंग का विश्लेषण करने पर मालुम पड़ता है कि भारत के उच्च शिक्षा संस्थान पढ़ाई लिखाई और उद्योगों से जुडाव के मामले में तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं किन्तु अनुसंधान के क्षेत्र में मात खा जाते है। एक ओर भारतीय प्रोफेसरों में रिसर्च पेपर प्रकाशित

करने की उद्यमिता और उत्साह कम है तो दूसरी ओर उनके पेपरों का साइटेशन इम्पेक्ट भी अपेक्षाकृत कम रहता है।

अगर हम विश्व रैंकिगों में भारतीय यूनिवर्सिटियों के खराब प्रदर्शन के बारे में शिक्षकों की राय जानने की कोशिश करें तो अनेक शिकायतें सुनने की मिलेंगी जो कि ध्यान देने योग्य हैं, यथा–विश्वविद्यालयों की लेबोरेटरियों और लायब्रेरियों में रिसर्च संसाधनों की कमी होना, टीचिंग और प्रशासनिक कार्यों का बोझा ज्यादा होना, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पिछले कई दशको से शोध कार्यो की हो रही उपेक्षा और विश्वविद्यालयों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ता हुआ दवाब।

विश्वस्तरीय रैंकिगों में भारतीय विश्वविद्यालयों की दुर्दशा पर दुखी और निराश होने से काम नहीं चलेगा। अगर हमें भारत को उच्च शिक्षा का आकर्षण केन्द्र बना कर लाखों विदेशी विद्यार्थियों को भारत में पढ़ने के लिये राजी करना है तो केन्द्र व राज्य सरकारों को मिलजुल कर उच्च शिक्षा को ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी। उच्चशिक्षा पर सकल राष्ट्रीय आय का 1 से 1.5 प्रतिशत खर्च करने से काम नहीं चलेगा, इसे अगले तीन वर्षों के भीतर 2.5 प्रतिशत करना होगा। अभी हाल में डा. कस्तूरी रंगन कमेटी ने नई शिक्षा नीति के प्रस्तावित मसौदे में शोध व अनुसंधान पर रू. 20,000 करोड़ की वार्षिक राशि खर्च करने का प्रस्ताव रखा है, किन्तु यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को देखते हुए पर्याप्त नहीं है।

भविष्य में विश्वस्तरीय रैंकिंगों में हमारा मुकाबला यूएसए, यूके और जर्मनी के साथ–साथ चीन, जापान, सिंगापुर और हांगकांग से भी होगा। हमें अच्छे यूनिवर्सिटी शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं को प्रतिष्ठाजनक स्थान देना होगा और देखना होगा कि वे देश में ही रह कर शिक्षण, शोध एवं अनुसंधान करें। उनका विदेश–गमन किसी भी हालत में रोकना होगा।